भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 363
27/03/2026 को उत्तरार्थ

विषयः- पंजाब में श्रीअन्न की खेती बढ़ाने हेतु योजनाएँ

***363. श्री सतनाम सिंह संधूः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की फसल पद्धति में विविधता लाने तथा धान जैसी अधिक जल की खपत करने वाली फसलों पर निर्भरता को कम करने के प्रयासों के रूप में पंजाब में श्रीअन्न (मिलेट) की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) पंजाब के किसानों को उच्च उपज देने वाले तथा सूखा-प्रतिरोधी श्रीअन्न के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और पिछले तीन वर्षों में इनका कितना वितरण किया गया है; और

(ग) क्या सरकार किसानों के लिए बेहतर आय के अवसर सृजित करने हेतु पंजाब में श्रीअन्न के मूल्य-वर्धित उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई विशिष्ट पहल क्या-क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पंजाब में श्रीअन्न की खेती बढ़ाने हेतु योजनाएँ" के संबंध में दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ माननीय सांसद श्री सतनाम सिंह संधू द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 363 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) सहित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत मिलेट (श्री अन्न) की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता सुधार के माध्यम से मिलेट (श्री अन्न) सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पंजाब सहित 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में एनएफएसएनएम के तहत कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। एनएफएसएनएम के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंजाब राज्य के लिए 34.60 लाख रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी + राज्य हिस्सेदारी) की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया था। एनएफएसएनएम-श्री अन्न के लिए स्वीकृत योजना में प्रदर्शन, बीज वितरण, बीज उत्पादन, आईएनएम और आईपीएम वितरण, प्रशिक्षण आदि के लिए राज्य के माध्यम से किसानों हेतु सहायता शामिल है।

इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को वर्ष 2013-14 से मूल हरित क्रांति वाले राज्यों यथा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि धान के जल सघन फसल क्षेत्र को मिलेट, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर परिवर्तित किया जा सके। वर्ष 2025-26 में, धान से अन्य वैकल्पिक फसलों में फसल विविधीकरण का समर्थन करने वाले विभिन्न कार्यकलाप के लिए पंजाब राज्य के लिए 103.75 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सेदारी + राज्य हिस्सेदारी) की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मिलेट की नई किस्मों/हाइब्रिड के प्रजनन बीज का उत्पादन सुनिश्चित करती है। विगत तीन वर्षों के दौरान मिलेट की कुल 110 किस्में जारी की गई हैं। उच्च उपज देने वाली, जलवायु-अनुकूल, जैव-फोर्टिफाइड किस्में या हाइब्रिड जो कीड़ों, कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी हैं, और अल्पावधि तथा मध्यम अवधि (10 वर्ष से कम पुरानी) की हैं जो मौजूदा प्रमुख किस्मों से बेहतर हैं, उन्हें एनएफएसएनएम के तहत बढ़ावा दिया जाता है। पंजाब में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान योजना के तहत मिलेट के कुल 140 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं।

सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और मिलेट आधारित उत्पादों में कार्यरत निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ संपूर्ण देश में मोटे अनाज की खेती, प्रसंस्करण और खपत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन – लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) कार्यान्वित कर रहा है और योजना का एक घटक 800 करोड़ रुपये (पीएलआईएसएमबीपी) के परिव्यय के साथ मिलेट-आधारित उत्पादों पर केंद्रित है। इस योजना के तहत, देश में 793.27 करोड़ रुपये की राशि के साथ 29 आवेदकों को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें पंजाब के कपूरथला, पटियाला और जालंधर जिलों की तीन परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत, 11 राज्यों के 21 जिलों में मिलेट और मिलेट- आधारित उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में चिह्नित किया गया है और मिलेट प्रसंस्करण करने वाले 10 राज्यों में 17 इन्क्यूबेशन केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। पीएमएफएमई के तहत, देश भर में मिलेट प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 91.20 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 4,612 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। पंजाब में, मिलेट इकाइयों के लिए 5 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को योजना के तहत 0.25 करोड़ रुपये की सब्सिडी को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईएमआर) हैदराबाद ने अपने उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और "न्यूट्रीहब" प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर के माध्यम से, रेडी-टू-ईट (आरटीई) और रेडी-टू-कुक (आरटीसी) उत्पादों (जैसे, मिलेट पास्ता, सेंवई, कुकीज़, पफ और फ्लेक्स) सहित मूल्य वर्धित प्रौद्योगिकियों का विविध पोर्टफोलियो विकसित किया है। ये प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां पंजाब सहित देश भर के स्टार्टअप, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और उद्यमियों को लाइसेंस देने के लिए उपलब्ध हैं। पंजाब के किसानों ने 2019 की शुरुआत में आईआईएमआर के न्यूट्रीहब द्वारा आयोजित " मिलेट मूल्य वर्धित उत्पादों और मार्केटिंग पर उद्यमिता विकास" पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका उद्देश्य जागरूकता सृजित करना और मिलेट क्षेत्र में स्टार्टअप और व्यवसाय के अवसरों पर प्रशिक्षण प्रदान करना था। आईसीएआर-आईआईएमआर, हैदराबाद ने मूल्य वर्धित मिलेट उत्पादों को बढ़ावा देने और मिलेट संवर्धन के लिए तकनीकी बैकस्टॉपिंग के साथ पहल में सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब स्थित संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि राज्य मिलेट के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के संबंध में उपभोक्ताओं और किसानों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए प्रदर्शनियों, मेलों, राज्य, जिला और ग्राम स्तर के शिविरों, स्कूलों और कॉलेजों में वार्ताओं का आयोजन कर रहा है। राज्य किसानों के लिए बेहतर आय के अवसर सृजित करने के लिए मिलेट के मूल्य वर्धित उत्पादों को भी बढ़ावा दे रहा है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने किसानों की आय और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य परियोजना "एमईआरए" (मिट्टी की उर्वरता के पुनर्स्थापन और स्वस्थ खाद्य पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए मिलेट) शुरू किया है। "एमईआरए" के मुख्य घटक जैविक मिलेट का उत्पादन, संवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन और खपत हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने अच्छी पॉपिंग क्षमता और उच्च पोषण मूल्य के साथ बाजरा और सोरघम की द्वि-उपयोग किस्में विकसित की हैं और इन्हें किसानों के बीच बढ़ावा दिया जा रहा है।

*****